>

Title: Need to improve the service conditions of Accredited Social Health Activists (ASHAs) under the National Rural Health Mission.

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): माननीय सभापति जी, मैं जो विषय सदन में उठाने जा रहा हूं, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सवाल पूरे देश से जुड़ा हुआ है। यूपीए के फर्स्ट चैप्टर में इस सरकार ने घोषणा की थी कि पूरे देश में रूरल हैल्थ मिशन के तहत आशाओं की नियुक्ति होगी। पूरे देश में लगभग 5 लाख 20 हजार आशाओं की नियुक्ति की गयी। पिछले लोक सभा के चुनाव से पहले तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने यह घोषणा की थी कि इनको 500 रुपये मानदेय दिया जायेगा। अभी जुलाई में वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी यह घोषणा की कि जल्दी ही इनके मानदेय की घोषणा की जायेगी।

मान्यवर, मुझे अफसोस है कि हमारा स्वास्थ्य सैक्टर सबसे नेगलेक्टेड सैक्टर है। मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि अमर्त्य सेन, जिनको नोबल पीस प्राइज मिला था, उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो चीजें अगर देश की ठीक हो जायें, तो उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह इसी सरकार की घोषणा और स्कीम थी, लेकिन पांच साल बीतने के बाद भी अभी तक इस सरकार ने उनके मानदेय की घोषणा नहीं की। मैं इस सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि वह उन्हें कम से कम 500 रुपये मानदेय दे और प्रदेश सरकारों को भी लिखे कि वे भी उन्हें 500 रुपये देने का काम करें।

मान्यवर, उन लोगों ने अभी नवम्बर में यहां पर प्रदर्शन भी किया था।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : रेवती रमन सिंह जी, आप संक्षिप्त मे अपनी बात कहिये।

श्री रेवती रमन सिंह : सभापति महोदय, मैं अपनी बात खत्म ही कर रहा हूं। अभी तक सरकार ने उसे संज्ञान में नहीं लिया और न ही कोई कार्रवाई की है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि उनको और भी सुविधाएं जैसे ड्रेस या प्रसव कराने के लिए किसी कमरे या बाथरूम की भी सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि घरों में कहीं अनहाइजिनिक जगह पर प्रसव नहीं कराया जा सकता। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि तत्काल उनकी मांग को पूरा करते हुए अन्य सुविधाएं, जो उन्होंने मांग की हैं, वे भी उन्हें प्रदान की जाये।